- Making extension services demand driven;
- Moving towards integrated extension delivery;
- Taking up capacity building programmes for extension institutions, personnel and farmers;
- Addressing gender issues in agriculture;
- Piloting new institutional arrangements for transfer of technology and
- Promoting use of information technology.

(c) Restructured extension system will be able to better serve the technological needs of the farmers.

Loss of Lives due to Cyclone in Gujarat

2510. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of lives lost as per latest assessment in the cyclones that hit the Kandla and other Gujarat Coasts in August last year;

(b) the number of applications for compensation and relief of victims' families; and

(c) the amount so far released from Prime Minister's Relief Fund for these victims and whether these are actually paid to the victims families?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) The Government of Gujarat has reported that, as per the latest assessment, 1751 persons reportedly died due to the cycloen of June, 1998. The State Government has provided ex-gratia relief amounting to Rs. 1005.85 lakh to the families/ heirs of the victims in 1172 cases. The State Government had received Rs. 651.50 lakh from the Prime Minister's Relief Fund for these victims and Rs. 538.00 lakh has been actually paid to the families of the victims.

हरित क्रांति में क्षेत्रीय असंतुलन

2511. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि हरित क्रांति से केवल सिंचित क्षेत्र को ही फायदा हुआ है और इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु क्या कार्रवाई कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) हरित क्रांति से मुख्यतया सिंचित क्षेत्रों को अंसिंचित या वर्षा सिंचित क्षेत्रों की तुलना में लाभ हुआ है जहां बुनियादी ढ़ांचे की बेहतर सुविधाएं सुलभ हैं।

(ख) सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिये असिंचित/वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास करने को उच्चतम प्राथमिकता दी है। "वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना" प्रमुख कार्यक्रम है जो देश के सभी प्रखंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिये फसल विकास योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। नौवीं योजना के दौरान, कृषि विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों की कृषि-जलवायुयीय स्थितियों के आधार पर क्षेत्रीय तौर पर भिन्न-भिन्न कार्यनीतियां अपनाना प्रतिपादित किया गया है।

उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग

2512. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "हरित क्रांति" के दौरान उर्वरकों का अंधाधुध प्रयोग हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरा-शक्ति प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रक्रिया को दूर करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) 1997-98 के दौरान भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटासियम (एन.पी.के.) के रूप में उर्वरक की औसत खपत प्रति हैक्टयर 87.46 कि॰ ग्रा॰ होने का अनुमान है। अन्य देशों के साथ की गई तुलना से पता चलता है कि पाकिस्तान (113 कि॰ ग्रा॰), बंग्लादेश (135 कि॰ ग्रा॰), नीदरलैण्ड (543 कि॰ ग्रा॰) और चीन (371 कि॰ ग्रा॰) जैसे देशों में उर्वरक की खपत कहीं अधिक है।

भारत में उर्वरक की खपत की लाभकारी प्रतिक्रिया है और अधिक उपज मिलती है, कृषि वैज्ञानिक उर्वरक पोषकों की अधिक खुराक की सिफारिश करते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है।

तथापि, सरकार उर्वरकों के संतुलित उपयोग की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है जिसमें मुद्रा की उर्वरता

बनाए रखने के लिए उर्वरकों का मुद्रा परीक्षण आधारित उपयोग, रासायनिक उर्वरकों, कम्पोस्ट, खाद तथा जैव-उर्वरकों का संयोजक उपयोग शामिल है।

Production of Kesari Dal

2513. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the production of Kesari Dal which is harmful for the human beings is increasing in several States;

(b) if so, whether the Indian Council of Agricultural Research have conducted any survey about its rapid production and effect on human beings;

(c) if so, facts and details thereof; and

(d) further reaction of the Government on the use of Kesari Dal in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE: (a) State-wise production of Kesari Dal in 4 major producing States during the last 3 years is given below:

Production (Thousand Tonnes)

State	1995-96	1996-97	1997-98
Bihar	115.2	158.4	133.8
Madhya Pradesh	254.8	337.7	48.0
Maharashtra	20.8	22.6	16.6
West Bengal	30.9	32.2	28.5
TOTAL	421.7	550.9	226.9

(b) and (c) A survey about production, consumption pattern and harmful effect of Kesari dal on human health was conducted in a sample of villages in Chattisgarh region of Madhya Pradesh by Indira Gandhi Agricultural University, Raipur in 1996. The major findings of survey are summarised below:

Families surveyed involved marginal, small and medium farmers. It was found that most families use Kesari as dal and some use it in the form of besan and bread. It is reported that those who used Kesari in bulk quantities as food during 1974-75 food deficit period have suffered due to lathyrism. As per report of survey, 15 people were found to be affected due to lathyrism. These were case 1974-75 and 1980-81. About 48% people surveyed were aware of the harmful affect of Kesari dal consumption.

It is to be mentioned that socio-epidemiological studies conducted in many other countries suggest that there is close association between consumption of Kesari Dal and Lathyrism in human beings.

(d) The ban on the sale and storage for sale of Kesari dal has been in operation since 1961 under Rule 44-A of the Prevention of Food Adulteration (PFA) Act.

गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछेक जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया जाना

2514. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कतिपय जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है;

(ख) क्या गुजरात के कच्छ तथा पंचमहल जिलों को सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्र की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है;

(ग) इन जिलों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही केन्द्रीय सहायता का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन जिलों को अधिसूचित करने पर भी विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में किसी भी जिले को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि 15 जिलों में 6135 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस समय राज्य में 7 जिलों की 25 तहसीलें सूखाग्रस्त हैं।

(ख) गुजरात सरकार ने कहा है कि कच्छ और पंचमहल जिलों के किसी भी क्षेत्र को अभी तक अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Private Participation in Nuclear Power Sector

2515. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether Government